दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 14 ▸ अंक : 4 ▸ गाजियाबाद, सितम्बर, 2018 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

सक्सेस करीना कपूर की अनसक्सेस लव स्टोरी.... P-8

पीएफ में 'पी एम आर पी वाई' सुविधा का लाभ शुरू के एक साल जिस भी कंपनी को नहीं मिल पाया था-अब मिलेगा

गाजियाबाद। 'लॉ ऑफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन उ. प्र. के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नरेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि जिन भी कंपनियों को 'पी एम आर पी वाई' सुविधा का लाभ शुरू के एक साल में नहीं मिल पाया है उनका पैसा कंपनी के अकाउंट में जल्द ही चला जायेगा। क्योंकि बहुत सी कंपनियों ने जानकारी के अभाव में इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाई थी उनको अप्रैल 2016 के बाद से जब तक का लाभ नहीं मिला है तब तक का पैसा कंपनी के अकॉउंट में चला जायेगा। सत्येन्द्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष एलएलएएयूपी ने कहा की जिस भी कंपनी को इसका लाभ नहीं मिला था उन्हें इसका लाभ मिलेगा तथा जो भी कर्मचारी अप्रैल 2016 के बाद नौकरी में आये है एवं यदि उन नए कर्मचारियों का यदि यूएएन अप्रैल 2016 के बाद का है तभी इस सुविधा का लाभ कंपनी को मिल पायेगा। सिंह ने आगे कहा की शुरूआत में पी एफ की साइट काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से लगभग एक साल बाद लोगों ने इस सुविधा का लाभ लेना शुरू किया है जिसके कारण पिछले एक साल का लाभ कंपनियों को नहीं मिल पाया था जिसके लिए विभाग ने अब आश्वासन दिया है की जल्द ही वह पैसा कम्पनियों के अकॉउंट में ट्रांसफर हो जायेगा। बैठक में आर सी माथुर, अशोक श्रीवास्तव, अरविन्द श्रीवास्तव, धर्मपाल, ओ पी व्यास, डॉ. एस एस उपाध्याय, शैलेश श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद थे।

❑ प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने कहा की जिस भी कंपनी को इसका लाभ नहीं मिला था उन्हें इसका लाभ मिलेगा तथा जो भी कर्मचारी अप्रैल 2016 के बाद नौकरी में आये है एवं यदि उन नए कर्मचारियों का यदि यूएएन अप्रैल 2016 के बाद का है तभी इस सुविधा का लाभ कंपनी को मिल पायेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बुधवार को एक नई योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार होने पर नकद राहत मिलेगी. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी. इस स्कीम से कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट, 1948 के तहत बीमित लोगों को लाभ होगा. मंत्रालय ने कहा कि भारत में नौकरी के मौजूदा पैटर्न को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. पहले जहां नौकरी लंबे समय की हुआ करती थी वहीं अब इसका पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट या अस्थाई हो गया है. इस प्रस्तावित योजना को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई (ईएसआईसी) बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई.

ईएसआईसी अलग से जारी करेगा आवेदन पत्र

इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी जैसे पात्रता, आवेदन का फॉर्मेट आदि बाद में अलग से जारी किया जाएगा. अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों और उसके परिवार के आधार को ईएसआईसी डेटाबेस में अपडेट करवाता है तो उसे हर कर्मचारी के हिसाब से 10 रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे. ईएसआईसी ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इससे एक ही व्यक्ति के कई जगह रजिस्ट्रेशन करवाने का झंझट नहीं रह जाएगा.

इलाज के लिए नहीं करना होगा इंतजार

इस कदम से बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को सुपर स्पेशियालिटी इलाज कराने के लिए ज्यादा दिनों का इंतजार अब नहीं करना होगा. बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर होने वाला खर्च भी ईएसआईसी ने 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है.

ईएसआईसी में 78 दिन योगदान करने वालों को मिलेगी सुपर स्पेशियालिटी इलाज की सुविधा

ईएसआईसी ने एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी जिससे कर्मचारियों को इलाज करवाने में सुविधा होगा. पहले सुपर स्पेशियालिटी इलाज के लिए जरूरी था कि नौकरी 2 साल पुरानी हो. अब इसे घटाकर 6 महीने कर दिया गया है. इस अवधि के दौरान ईएसआईसी में 78 दिन का योगदान सुपर स्पेशियालिटी इलाज के लिए जरूरी होगा.

❑ श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी

हालांकि, अगर बीमित व्यक्ति के आश्रितों को सुपर स्पेशियालिटी इलाज के मामले में कर्मचारी की नौकरी 1 साल पुरानी होना और ईएसआईसी में 156 दिनों का योगदान जरूरी होगा.

आधे से ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों के यूएएन से नहीं जुड़े आधार-बैंक अकाउंट

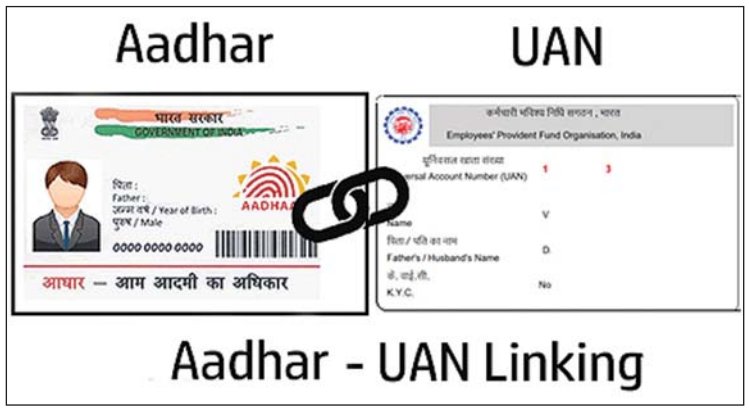

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 50 फीसदी से अधिक सदस्यों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ 'नो योर कस्टमर' (केवाईसी) डीटेल अटैच नहीं है। इसकी वजह से इन्हें ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

सरकार ने ईपीएफओ के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को पीएफ सदस्यों के यूएएन का 100 फीसदी केवाईसी सीडिंग का आदेश दिया था। केवाईसी को यूएएन के साथ जोड़ना अनिवार्य है और ऐसा ना करना दंडनीय अपराध है।

तेज और सरल सुविधाएं देने के लिए ईपीएफओ ने 2014 में सभी सदस्यों को 12 अंकों वाले यूएएन देने की शुरूआत की थी। भविष्य निधि से जुड़ी सेवाओं के लिए यूएएन बहुत महत्वपूर्ण है।

इसका सही लाभ केवाईसी सीडिंग के बाद मिलता है। यानी आधार, बैंक अकाउंट, पैन और मोबाइल नंबर यूएएन के साथ जुड़ा हो। यदि केवाईसी डीटेल्स यूएएन के साथ दर्ज हो तो सदस्य अपने मोबाइल के जरिए पीएफ खाते की त्वरित जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन दावा भी फाइल कर सकते हैं।

दिल्ली स्थित रीजनल ऑफिस ने अब इस काम की शुरूआत मिशन मोड में की है और सभी संगठनों को लेटर, ई-मेल और रटर के जरिए सूचना दी गई है। 9 हजार प्रतिष्ठानों को हर दिन मेसेज भेजा जा रहा है। इसके लिए एक विशेष सेल का गठन भी किया गया है। रीजनल पीएफ कमिश्नर निधि सिंह ने कहा कि यूएएन के साथ केवाईसी लिंकिंग अनिवार्य है और इसे ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

रीजनल पीएफ कमिश्नर निधि सिंह ने कहा कि यूएएन के साथ केवाईसी लिंकिंग अनिवार्य है और इसे ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

श्रम—जगत

02 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, सितम्बर, 2018

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7613.42
Semi Skilled	8374.77
Skilled	9381.06

Engineering (50 to 500)

w.e.f. 01/02/2018 To 31/07/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8903.10
Semi Skilled	9776.65
Skilled	10853.64

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9333.89
Semi Skilled	10267.28
Skilled	11200.67

Delhi Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16858.00
Semi Skilled	15296.00
Un-Skilled	13896.00

Rajasthan Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages

w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

सेंसेक्स टुडे : बाजार में गिरावट जारी, 200 पॉइंट टूटा सेंसेक्स

नई दिल्ली। एशियाई बाजार में कमजोर रुख के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, रियल्टी, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स सोमवार को शुरूआती कारोबार में 200 अंक से अधिक गिरा। रुपये की गिरावट ने भी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में बढ़त के साथ 36,924.72 अंक पर खुला। हालांकि जल्दी ही 210.22 अंक यानी 0.57 प्रतिशत लुढ़क कर 36,631.38 अंक पर आ गया। पिछले चार कारोबार

दिवस में सेंसेक्स 1,249.04 अंक गिरा था। इसी प्रकार, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरूआती दौर में 65.50 अंक यानी 0.59 प्रतिशत गिरकर 11,077.60 अंक पर रहा।

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को शेयर बाजार के लिए बड़ा दिन था। तब हरे निशान पर खुलने के बाद भी शेयर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई थी। दोपहर में सेंसेक्स अचानक 1500 पॉइंट्स तक टूट गया था। गिरावट की मुख्य वजह यस बैंक के सीईओ राणा कपूर + के खिलाफ आरबीआई की सख्ती मानी जा रही थी।

बता दें कि मोहर्रम की छुट्टी के बाद शुक्रवार को खुला शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। तब सेंसेक्स 279.62 अंक (0.75%) जबकि निफ्टी 91.25 अंक (0.81%) टूटकर क्रमशः 36,841.60 और 11,143.10 अंक पर बंद हो गया था।

जिले के स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों की हुई पहचान

गाजियाबाद। लखनऊ से प्रशिक्षण लेकर आए शिक्षक स्कूल छोड़ चुके छात्र-छात्राओं को पढ़ाएंगे। जनपद में इस बार 273 छात्र-छात्राओं की पहचान की गई है। जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं ये सभी बच्चे कक्षाओं में प्रतिदिन सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान व गणित सहित सभी विषयों का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए शासन से बजट आवंटित किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने जनपद में पिछले माह हाउस होल्ड सर्वे किया था। इसमें स्कूल छोड़ चुके या कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान की गई थी। इसके बाद इन सभी बच्चों का ब्योरा निकालकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया था। इस बार पिछले साल की तुलना में आधे ही बच्चे ऐसे निकले जो कभी स्कूल नहीं गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस सर्वे में छह वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की पहचान की जाती है।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008

A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS &

PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent

in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computerized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end service includes;

- ❑ Payroll
- ❑ TDS
- ❑ ESI Act
- ❑ EPF Act
- ❑ Minimum Wages Act
- ❑ Bonus Act
- ❑ Payment of Gratuity Act
- ❑ Standing Order
- ❑ Workmen Health & Safety Policy
- ❑ First Aid Training & Certificates
- ❑ Factory Plan & Site Plan
- ❑ Factory Act-1948
- ❑ Shop & Establishment Act

Our Website : www.legalipl.com, **CMD -** 9818036460 / 9818697406

H.O. : SH-295, 1st FLOOR, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD (U.P.) INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794,
Mobile : 9910771102/04

B.O. : D-129, 1st Floor, Sector-10, NOIDA, GAUTHAMBUDH NAGAR, (U.P.) INDIA.
Ph. : 0120-4222307

E-mail : legalipl@yahoo.com, legaliplho@yahoo.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गासिक सगाचार पत्र
दिल्ली-एनसीआर
03
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, सितम्बर, 2018

दो तक केवाईसी पूरी कर लें पीएफ खाताधारक

पीएफ विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसल की गई

कानपुर। पीएफ खाताधारक जल्द ही नो योर कस्टमर (केवाईसी) की औपचारिकताएं पूरी कर लें। विभाग की ओर से जारी डेड लाइन दो अक्टूबर तक केवाईसी पूरी नहीं होने पर खाताधारकों को परेशान हो सकती है। उन्हें पीएफ का क्लेम नहीं मिल पाएगा। कानपुर रीजन में करीब दो लाख पीएफ खाताधारक हैं।

सूत्रों के मुताबिक मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में महज 35 फीसदी पीएफ खाताधारकों के ही आधार लिंक हैं।

वहीं, करीब 40-50 फीसदी के बैंक अकाउंट लिंक हैं। ऐसे में अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के केवाईसी पूरी नहीं है। आधार लिंक न होने से खाताधारक को ज्यादा परेशानी है। इसके लिए विभाग ने काम शुरू कर दिया है।

दो अक्टूबर तक विभाग में शनिवार की छुट्टी और अन्य किसी भी कर्मचारी और अफसर की छुट्टी कैंसल कर दी गई है। विभाग की मंशा है कि खाताधारकों की केवाईसी हर हाल में पूरी हो जाए।

ऑनलाइन पूरी कर सकते केवाईसी की औपचारिकता

यदि पीएफ खाताधारक का यूनीवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) सक्रिय है और उसने लॉगइन बना रखी है तो वह आनलाइन घर बैठे भी केवाईसी पूरी कर सकता है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन करके फार इंप्लाई ऑपशन में जाना होगा। इसी तरह इंप्लायर भी फार इंप्लायर ऑप्शन में जाकर ऐसे सभी कर्मचारियों जिनके केवाईसी पूरी नहीं है, उसे पूरा कर सकता है।

इसलिए जरूरी है केवाईसी

पीएफ विभाग सभी प्रकार के दावों (पीएफ एडवांस या अंतिम दावा) के भुगतान की पूरी प्रक्रिया को आनलाइन करना चाहता है। आनलाइन भुगतान में के वाईसी (पीएफ खाताधारक का आधार कार्ड पैन, बैंक अकाउंट का डिटेल) जरूरी है। इसके बिना दावा भुगतान संभव नहीं है। दावा आनलाइव आने पर इनके मिलान से भुगतान कम समय में हो सकेगा।

बाल श्रम रोकने की दिशा में भारत कर रहा प्रयास

- अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दी जानकारी
- 14 देशों ने 2017 में बाल श्रम खत्म करने की दिशा में किए प्रयास

वाशिंगटन। भारत उन 14 देशों में हैं जिसने 2017 में बाल श्रम के सबसे खराब स्वरूपों को खत्म करने की दिशा में प्रयास किए हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने 'चाइल्ड लेबर एंड फोसर्ड लेबर' की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इस रिपोर्ट को दुनिया भर में बाल मजदूरी की स्थिति पर हुआ अब तक का सबसे विस्तृत अध्ययन माना जा रहा है। बता दें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनियाभर में दस में एक बच्चा यानी 15.2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में फंसे हुए हैं।

विभाग ने 132 देशों में बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए हो रहे प्रयासों का नए मानकों के तहत विश्लेषण किया था। भारत के साथ कोलंबिया, प्राग जैसे 14 देश ही इन मानकों पर खरे उतरे हैं। इन नए मानकों में कानूनी और नीतिगत सुधार शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने बाल मजदूरी कानून में संशोधन किया है। बाल मजदूरी कानून के उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 'नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन' भी शुरू किया।

हालांकि, अब भी भारत में बच्चों से

जबरन मजदूरी कराई जा रही है। उन्हें पत्थर ढोने के साथ ही ईट की भट्ठियों में काम कराया जाता है इसलिए भारत सरकार से चाइल्ड लेबर एक्ट में उन सभी कामों को शामिल करने की अपील की गई है जिसमें बच्चे असुरक्षित वातावरण में काम करते हैं।

मोजर बेयर के कर्मचारी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे

ग्रेटर नोएडा। नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) ने मोजर बेयर फैक्ट्री को दिवालिया घोषित कर दिया है। इस फैक्ट्री के कर्मचारी इंसाफ के लिए अब उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कर्मचारियों ने बताया कि एनसीएलटी ने अपना फैसला सुनाते समय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा है। कर्मचारी दिल्ली पुलिस की इकॉनिमिकल आफेंस विंग में भी अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे।

सूरजपुर उद्योग विहार स्थित फैक्ट्री के प्रबंधक सतेंद्र नागर ने बताया कि 1998 में नोएडा फेस दो व 2002 में ग्रेटर नोएडा उद्योग विहार में फैक्ट्री लगाई गई थी। 2012 तक आप्टिकल मीडिया बनाने के क्षेत्र में फैक्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी व दूसरे पायदान पर काबिज थी। इस इकाई में 11 हजार स्थाई कर्मचारियों के सहयोग से यहां डीवीडी, पेन ड्राइव, एलईडी उत्पाद, सोलर पावर, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस आदि दिवालिया घोषित करने का स्वांग रचना शुरू कर दिया। नवंबर 2017 में प्रदूषण विभाग के नोटिस का हवाला देकर फैक्ट्री में तीन दिन की छुट्टी कर दी। इसके बाद इकाई को पूरी तरह से बंद घोषित कर दिया। कर्मचारियों के पक्ष में पेड लीव का नोटिस चस्पा कर दिया, लेकिन एक साल से अधिक समय से वेतन भी नहीं दिया गया। इससे कर्मचारियों की माली हालत भी दयनीय है। करीब ढाई हजार कर्मचारियों का परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया। इसके अलावा वेंडर इकाइयों पर भी गहरा असर पड़ा है। इन इकाइयों में काम करने वाले करीब 30 हजार से अधिक कर्मचारी भी प्रभावित हो गए हैं।

नई कंपनी शुरू करने का आरोप : मोजर बेयर के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि इकाई को बंद करने की प्रक्रिया को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। बैंक ऋण लेकर दूसरे नाम से मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाई गई है। ग्रेटर नोएडा की इकाई में उत्पादन कम कर मध्य प्रदेश में काम बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहा। इस दौरान गौतमबुद्ध नगर की दोनों काई पर ऋण बढ़कर 4356 करोड़ रुपये पहुंच गया।

कर्मचारी कल्याण का मुद्दा ले जाएंगे न्यायालय

कर्मचारियों का कहना है कि बैंक सेटलमेंट के साथ कर्मचारी हितों का ध्यान रखते हुए न्यायालय के समक्ष एक साल का बकाया वेतन, अगले दो साल की ग्रास सैलरी का पूरा भुगतान, सभी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, ईपीएफ का फुल सेटलमेंट करने की गुहार लगाएंगे। इसके अलावा निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी।

वकील को थप्पड़ मारने पर पूरी चौकी लाइन हाजिर

- नोएडा में एसएसपी ने की कड़ी कार्रवाई, आरोपित को किया निलंबित

नोएडा। गढ़ी चौखंडी के रहने वाले वकील महेंद्र सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में एसएसपी डॉ. अजय पाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गढ़ी चौखंडी पुलिस चौकी पर तैनात सभी कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। अधिवक्ता को सिपाही द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद अधिवक्ता लामबंद हो गए। अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया, न्यायालय के गेट पर ताला जड़ दिया, एसएसपी व डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला न्यायालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग की पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। एसएसपी ने कांस्टेबल अशोक बालियान, अशोक शर्मा, फैजुल हसन, राजकुमार सिंह, फिरोज खान, यतेंद्र कुमार वराज बहादुर को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन भेज दिया गया है। वहीं, चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह वीआईपी ड्यूटी में दिल्ली होने के कारण लाइन हाजिर होने से बच गये। जबकि वकील को थप्पड़ मारने के आरोपित कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार को आइजी के निर्देश पर एसएसपी ने लाइन हाजिर करते हुए देर रात निलंबित कर दिया था। सीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि वायरली वीडियो की भी जांच की जा रही है। जल्द ही जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी जायेगी।

यह है मामला : सेक्टर 121 स्थित क्लियो काउंटी के लिये महेंद्र सिंह की 12 वीघा जमीन अधिग्रहित की गई है। महेंद्र सिंह ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, लेकिन स्टे नहीं मिला है। वह सोसायटी की जमीन को विवादित होने की पर्ची बांट कर लोगों से फ्लैट लेने से बेचने की अपील कर रहे हैं। बिल्डर की शिकायत पर फेस-3 कोतवाली पुलिस ने पर्ची बांटने वाले दो लोगों को पकड़ कर गढ़ी चौखंडी पुलिस चौकी लाई। उन्हें छुड़ाने पहुंचे वकील को कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार ने थप्पड़ मार दिया था।

पॉलीथिन ने दो घंटे रोक दिया रेलों का संचालन

मथुरा। पॉलीथिन की वजह से दिल्ली-आगरा रेमार्ग को ठप पड़ गया। दिल्ली से आगरा जा रही मालगाड़ी के डिब्बों में पड़ी पॉलीथिन उड़कर ओएचई पर चिपक गई। इससे दो घंटे तक अप और आधा घंटा डाउन लाइन पर यातायात प्रभावित रहा। टावर वैगन से ओएचई से पॉलीथिन हटाने के बाद ही ट्रैक सामान्य हो सका।

मालगाड़ी दिल्ली से आगरा जा रही थी। मालगाड़ी के खाली डिब्बों में पॉलीथिन पड़ी हुई थीं। यह पॉलीथिन ट्रेन के डिब्बों से उड़कर पलवल से होडल के मध्य कई जगहों पर ओएचई से चिपक गई। ओएचई पर पॉलीथिन चिपक जाने के कारण ट्रेनों का संचालन ठप हो गया और ट्रेनों को पलवल पर रोक दिया गया। जानकारी पर अधिकारियों ने टावर वैगन से पलवल से होडल के बीच ओएचई से पॉलीथिन हटवाया। कोसीकलां रेलवे स्टेशन पर

मालगाड़ी के डिब्बों से पॉलीथिन साफ की गई, इसके बाद उसे रवाना किया गया। इस दौरान डाउन रूट की दिल्ली की ओर जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस आधा घंटा प्रभावित रही। अप ट्रैक पर दिल्ली से मथुरा की ओर जाने वाली ताज एक्सप्रेस, गोल्डन टेंपल दो-दो घंटे, समता एक्सप्रेस आधा घंटा प्रभावित हुई। रेलवे के पीआरओ डॉ. संचित त्यागी ने बताया कि पॉलीथिन हटाने में करीब एक घंटे का समय लगा। इसके बाद ट्रैक को सुचारू कराया गया।

सभी वाहनों के बीमा के साथ 15 लाख का दुर्घटना बीमा अनिवार्य

नई दिल्ली। अब मोटर चालित वाहन जैसे स्कूटर, बाइक, कार और वाणिज्यिक वाहनों के बीमा के साथ स्वामी-चालक का 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य होगा। इसके लिए वार्षिक प्रीमियम 750 रुपये तय की गई है। इससे दुर्घटना होन पर मृतक के परिजनों को बेहद आवश्यक वित्तीय मदद मिल सकेगी। हालांकि वाहनों का बीमा करना महंगा भी हो जाएगा। बीमा क्षेत्र की नियामक एजेंसी इरडा ने अहम कदम उठाते हुए गुरुवार को नया दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

इरडा ने कंपनियों को कहा है कि 25 अक्टूबर तक सभी कंपनियों के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा। अभी दोपहिया वाहनों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि एक लाख और कारों के लिए दो लाख रुपये है। कई बीमा कंपनियां व्यक्तिगत बीमा की राशि को बढ़ाने का विकल्प देती हैं, लेकिन प्रीमियम काफी ज्यादा होता है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि वाहन मालिकों के लिए दुर्घटना बीमा की सीमा एक लाख से बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये से ज्यादा की बीमा कवरेज भी दे सकती हैं और इसके लिए अलग से प्रीमियम तय कर सकती हैं। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ तपन सिंघल ने इसे सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या उसके परिवार को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक मदद मिल सकेगी।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
Editorial
04 P.
गाजियाबाद, सितम्बर, 2018

सम्पादकीय

सीमा पर बर्बरता

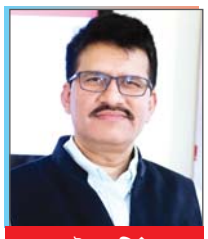

सत्येन्द्र सिंह

इमरान खान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब शायद पाकिस्तान के रुख में बदलाव आएगा और वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने और उसे मित्रता के स्तर पर ले जाने का प्रयास करेगा। मगर अब तक पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, जिससे कहा जा सके कि वह संबंधों में सुधार को उत्सुक है। उल्टे हर कुछ दिन में पाकिस्तान की ओर से कोई न कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है, जिससे संबंधों में सुधार की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू के नजदीक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की जिस तरीके से हत्या कर दी, उससे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को सहज बनाने के बजाय उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। यह अचानक गोलीबारी में हुई किसी जवान की मौत नहीं है। जैसी खबरें आई हैं, उनसे यही लगता है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सुनियोजित तरीके से घात लगा कर भारतीय जवान को निशाना बनाया, उस पर तीन गोलियां दागीं और फिर गला रेत कर उसकी मौत सुनिश्चित की। यह समझना मुश्किल है कि भारतीय जवान की हत्या करने वाले पाकिस्तानी सैनिक किस स्तर की नफरत से भरे थे या किसके आदेश से और क्यों ऐसा कर रहे थे। भारतीय सैनिकों के साथ ऐसी बर्बरता पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय जवानों को मार डाला और उनका सिर काट कर ले गए या उनके शव को क्षत-विक्षत कर डाला। जबकि इस बारे में अंतरराष्ट्रीय कानूनों में साफ कहा गया है कि मुठभेड़ या किसी भी दूसरी वजह से मारे गए व्यक्ति के शव के साथ बर्बरता अनुचित है। उस पर पाबंदी है। हर हाल में शवों का सम्मान किया जाना चाहिए। मगर पाकिस्तान की हरकतों से ऐसा लगता है कि न उसे किसी नैतिकता की परवाह है, न अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानना उसे जरूरी लगता है। विडंबना यह है कि सीमा पर ऐसी हरकतों के बाद अपनी गलती स्वीकार करने और भविष्य में ऐसा न होने देने की कोशिशों के बजाय पाकिस्तान आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अपना राग अलापने लगता है। हर कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की ओर से कोई न कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जाती है, जिससे न केवल सीमा पर टकराव की स्थिति बन जाती है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया की कोशिशें भी बाधित होती हैं। पाकिस्तान की इस तरह की हरकतें कई शक्लों में सामने आती हैं। कभी वहां के कोई राजनेता या सरकार में मंत्री ऐसा बयान दे देते हैं, जिसका मकसद ही तनाव पैदा करना होता है, तो कभी सीमा पर गोलीबारी करके भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिशें की जाती हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान में स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां चलाने वाले आतंकी गिरोहों की मदद करना उसका एक मुख्य शगल रहा है। यह बेवजह नहीं है कि जब भी भारत की ओर से दोनों देशों के बीच संबंधों को सहज बनाने की कोशिश होती है, इस संबंध में कूटनीतिक पहलकदमी होती है, तो वह पाकिस्तान के नकारात्मक रवैए की वजह से खटाई में पड़ जाती है। अगर पाकिस्तान सचमुच अमन चाहता है, तो उसे अपने सैनिकों की हरकतों को नियंत्रित करना ही पड़ेगा।

आरएसएस के मंच पर चढ़ने से क्यों डर गये राजनीतिक दल?

श के राजनीतिक दल इस कदर पूर्वाग्रहों से प्रेरित हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से संवाद से भी कतराते हैं। दलों के नेताओं को लगता है कि यदि संवाद स्थापित कर लिया तो उनके पूर्वाग्रहों के दावे संदिग्ध लगने लगेंगे। गैर भाजपाई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आमंत्रण को ठुकरा कर कुछ ऐसा ही किया है। आरएसएस ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुखों को 'भविष्य का भारतः आरएसएस का दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें कांग्रेस सहित किसी भी दल के नेता ने शिरकत नहीं की। आरएसएस की आलोचना करने वाले राजनीतिक दलों को लगता है कि यदि उन्हीं के मंच पर चढ़ गए तो उनकी आलोचना का हथियार भौंथरा हो जाएगा। जिसे वे गाहे-बेगाहे आरएसएस के जरिए भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। दरअसल दूसरे शब्दों में कहें तो विपक्षी दलों ने आरएसएस को घेरने को एक महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय मौका गंवा दिया। आरएसएस के मंच से ऐसे सवाल दागे जा सकते थे, जिन्हें गाहे-बेगाहे दूसरे माध्यमों से प्रचारित किया जाता रहा है। आरएसएस ने आगे बढ़कर यह मौका सभी प्रमुख विपक्षी दलों को मुहैया कराया था। इसमें शिरकत नहीं करना यह भी दशार्ता है कि राजनीतिक दल देश की समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से संवाद के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करने से कतराते हैं। राजनीतिक दलों के आरोपों की बुनियाद इतनी खोखली नहीं होनी चाहिए कि संवाद के भय से ही धराशायी हो जाए। यदि आरएसएस से इतना ही परहेज है तो उसे उसी के मंच से उजागर करके सवालों के जवाब मांगने चाहिए थे।

इससे बचकर निकलने से यह साबित होता है कि आरएसएस के खिलाफ लगाए जाने वाले तमाम आरोपों में दम नहीं है, या फिर विपक्षी दलों का बातचीत के माध्यम से समस्याओं की तह तक जाने में भरोसा नहीं है। कांग्रेस महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का संबंध संघ परिवार से होना बताती रही है। इसी तरह अन्य दल भी आरएसएस को कट्टर हिन्दुवादी बताते हुए हिन्दु आतंकवाद को फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं। आरएसएस पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ विषवमन करने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। आरएसएस को महिला विरोधी ठहराते हुए महिलाओं को इसमें प्रवेश वर्जित होने के आरोप भी लगते रहे हैं।

भाजपा पर भी यह आरोप लगता रहा है कि आरएसएस पर्दे के पीछे से सरकार चलाती है, जबकि कहने को सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन होने का दंभ भरती है। संघ ने ही एक तरह से इन सवालों को उठाने का मंच मुहैया कराया था। सच्चाई यह है कि आरएसएस पर आरोप लगाने वाले दल भी दूध के धुले नहीं हैं। यदि संघ परिवार पर आरोप लगाए जाते तो कई सवालों के जवाब उसी मंच के जरिए दलों के नेताओं को भी देने पड़ते।

कांग्रेस सहित दूसरे दलों पर भी वोटों की खातिर अल्पसंख्यकों को जायज-नाजायज पक्ष लेते हुए ध्रुवीकरण का आरोप लगता रहा है। यहां तक कि कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों पर अल्पसंख्यकों के वोटों की खातिर दबे-छिपे तरीके से आतंकवादियों की पैरवी तक करने के आरोप लगते रहे हैं। बंगलादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भी भाजपा ने दूसरे दलों से देश की एकता-अखंडता से समझौता करने के आरोप लगाए हैं।

इन सबसे इतर कांग्रेस की कमजोर कड़ी भ्रष्टाचार रही है। सोनिया और राहुल गांधी और इनके दामाद रार्बट वाड्रा सहित कई वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। बैंकों का हजारों करोड़ लेकर चंपत हुए विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगौड़ों को प्रश्रय देने के आरोपों से भाजपा के साथ कांग्रेस भी लपेट में है। कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं को अंदाजा था कि यदि संघ से जवाब मांगे तो कई सवालों का जवाब उन्हें भी देना पड़ेगा। मंच के जरिए एक तरफा सवाल संभव नहीं है। इसमें भी खतरा यह होता कि संघ परिवार की ओर से उठाए गए मुद्दे भारी नहीं पड़ जाएं। इससे विपक्षी दलों के नेताओं और ज्यादा फजीहत होती। आरएसएस का पदार्फाश करने के बजाए खुद ही सवालों के चपेट में आ सकते थे। शायद यही वजह रही कि एक भी विपक्षी दल के नेता ने आरएसएस का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। यह इस बात का भी संकेत है कि राजनीतिक दल वास्तविक चुनौतियों से किस कदर मुंह चुराते हैं।

आरोप केवल वोट बैंक बनाने का जरिया मात्र रह गए हैं। इसकी तह तक जाने को कोई तैयार नहीं है। कोई भी दल मंच साझा करके दूसरे के विचार और जवाब सुनने तक को राजी नहीं है। समस्याओं और विचारों के प्रति ऐसा पूर्वाग्रह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति नुकसान देय है, जहां कोई दूसरे की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी कोई समस्या या विचार नहीं है, जिसमें परिवर्तन बातचीत के जरिए नहीं किया जा सकता हो।

लोकतांत्रिक पद्धति अपनाए जाने की प्रमुख वजह ही यही है कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से संवाद से हल हो सके। पंचायत से लेकर संसद तक की बुनियाद इसी पद्धति पर रखी गई ताकि मनमानी से बचा जा सके। यहां तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए संगठन बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उस मुद्दे के हर पहलू पर गंभीरता से विचार-विमर्श होता है। इसके जरिए देशों के बीच बातचीत से समाधान के रास्ते तलाश करते हुए युद्धों तक के मसले सुलझाए गए हैं।

यही वजह भी यह संगठन आज विश्व की सबसे बड़ी सबकी आवाज सुनने वाली संस्था बनी हुई है। देश की समस्याओं को सुलझाना है तो आपसी संवाद बेहद जरूरी है। संवाद नहीं होने से ही दूरियां और गलतफहमियां लगातार बनी रहती हैं। जबकि आरएसएस हो या विपक्षी दल, सभी का उद्देश्य देश में अमन-चैन और तरक्की कायम रखना है।

बच्चों के बोझ को कम कर सकता है स्कूल बैग का नया डिजाइन

स्कूल बैग का भारी वजन बच्चों के लिए हमेशा एक समस्या रही है। भारतीय शोधकताओं ने अब स्कूल बैग का ऐसा डिजाइन तैयार किया है जो बच्चों के कंधे और रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मददगार हो सकता है। इस बैग को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें भारी किताबों को रीढ़ के करीब और हल्की पुस्तकों को रीढ़ से दूर रखा जा सकता है। बैग की पट्टियों को इस तरह लगाया गया है जिससे बैग का निचला सिरा कमर से दो सेंटीमीटर ऊपर रहता है। पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में औद्योगिक और उत्पाद डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र के शोधकर्ता ईशांत गुप्ता ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि "हमने रीढ़ और कंधों से भार को कम करने और इसे पेडू क्षेत्र में वितरित करने के लिए एक आंतरिक फ्रेम बैग में शामिल किया है। नया डिजाइन धड़ पर भी भार को समान रूप से वितरित करने में मददगार होगा।" पहले के अध्ययनों में मनुष्यों में ऊर्जा खपत का संबंध धड़ के आगे की ओर

झुकाव से पाया गया है। पारंपरिक स्कूल बैग बैकपैक लोड को शरीर के द्रव्यमान के केंद्र के करीब रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चाल के साथ-साथ ऊर्जा व्यय में परिवर्तन होता है। इस तरह के बैग उठाते समय शरीर आगे की ओर झुक जाता है, जहां शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर, खोपड़ी और बैग के वजन को संतुलित करना होता है। नए डिजाइन में रीढ़ की हड्डी को ऊपरी शरीर के वजन को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है और कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अध्ययन में 11 से 13 साल के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों में संशोधित बैग और मौजूदा बैग्स के बीच चाल संबंधी मापदंडों, शरीर की मुद्रा, धड़ के कोण और ऊर्जा व्यय अंतर की जांच की गई है। शरीर के 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की लोडिंग स्थितियों के तहत नए और मौजूदा बैग्स का 26 बच्चों में परीक्षण किया गया है। अपने शरीर के 30 प्रतिशत वजन के बराबर भारी मौजूदा बैग उठाने वाले बच्चों में ऊर्जा व्यय सबसे ज्यादा होता है। जबकि, अपने शरीर के 30 प्रतिशत वजन के बराबर संशोधित बैग उठाने पर ऊर्जा व्यय कम पाया गया है। अध्ययनकताओं के अनुसार, संशोधित बैग के उपयोग से 6.7 कैलोरी प्रति मिनट ऊर्जा की खपत होती है, जबकि मौजूदा बैग के साथ 8.4 कैलोरी प्रति मिनट ऊर्जा खर्च होती है। नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में ऑथोर्पेडिक्स के प्रोफेसर डॉ. दविंदर सिंह के अनुसार, "शोधकताओं ने बैकपैक वजन का अध्ययन करते समय कई मानकों पर विचार किया है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता को यह पता हो कि अपने बैग को सही ढंग से कैसे पैक किया जाना चाहिए। आमतौर पर बच्चों के बैग का वजन उनके शरीर के वजन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भारी बैग पॉस्चर संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है।" शोधकर्ताओं के अनुसार, संशोधित बैकपैक सीधे खड़े होने की मुद्रा, सामान्य चाल और ऊर्जा खपत में कमी को सुनिश्चित कर सकता है, जिससे स्कूली बच्चों में पीठ दर्द और थकान के कारणों को कम किया जा सकता है। यह अध्ययन शोध पत्रिका करंट साइंस में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं में पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ईशांत गुप्ता एवं प्रवीण कालरा के अलावा मुंबई स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जुड़े रऊफ इकबाल शामिल थे।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

05 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, सितम्बर, 2018

पैन, आधार और यूएएन में नाम अलग-अलग है तो ऑनलाइन नहीं निकाल पाएंगे पीएफ

ऑनलाइन पीएफ निकासी की सुविधा होने के बावजूद कई लोगों को पीएफ ऑफिस भेजा जा रहा है। कारण, वो ईपीएफओ की वेबसाइट पर केवाईसी अपलोड नहीं कर सके। केवाईसी अपलोड किए बिना ऑनलाइन पीएफ निकालना संभव नहीं है। ईपीएफओ वेबसाइट पर जाने के बाद ऑनलाइन केवाईसी डिटेल भरने का विकल्प मिलता है। खाताधारकों को बैंक अकाउंट, पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि जमा करने को कहा जाता है। लेकिन, ये डीटेल्स देते वक्त कुछ खाताधारकों के पैन और आधार नंबर वेरिफाइड नहीं हो रहे हैं। इसलिए उनका केवाईसी अपलोड नहीं हो पा रहा।

इसलिए ऑनलाइन नहीं निकल पा रहा पीएफ

ईपीएफओ टेक्निकल डिपार्टमेंट के राजेश पिल्लई ने इसके मुख्य कारण के बारे में बताया, 'यूएएन, पैन और आधार के डीटेल्स एक-दूसरे से पूरी तरह मिलने चाहिए। अगर इनमें दर्ज नाम या कोई दूसरे डीटेल्स अलग-अलग हैं तो सिस्टम इन्हें स्वीकार ही नहीं करेगा।' इसलिए, अगर इन तीनों में डीटेल्स एक जैसे नहीं होकर कुछ भी अलग है तो आप ईपीएफओ की वेबासाइट पर केवाईसी अपलोड नहीं कर पाएंगे।

ऐसे सुधरवाएं डीटेल्स

ऑनलाइन केवाईसी समिट करने के लिए आपको तीनों डॉक्युमेंट्स के डीटेल्स सुधरवाकर एक जैसे करने होंगे। इसके लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर जॉइंट डेक्लरेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसे पीएफ ऑफिस में जमा करवाने पर यूएएन डेटाबेस में डीटेल्स सुधर जाएंगे और फिर आप ऑनलाइन केवाईसी जमा कर पाएंगे। इस लिंक पर जाकर आप जॉइंट डेक्लरेशन फॉर्म भर सकते हैं।

आधार सीडिंग सेंटर्स से लें मदद

इस फॉर्म पर आपके एंप्लॉयर का सिग्नेचर चाहिए होगा। साथ ही, जरूरी दस्तावेज भी अटैच करने होंगे। इस प्रक्रिया का आसान बनाने के लिए ईपीएफओ ने अहमदाबाद के दफ्तरों में आधार सीडिंग सेंटर्स खोल रखे हैं। अगर हर जगह आपका नाम एक जैसा नहीं है तो आप आधार कार्ड लेकर किसी सेंटर पर जाएं। यहां आपका बायोमेट्रिक चेक कर डीटेल्स सुधार दिए जाएंगे। अभी ईपीएफओ के मनीनगर, नरोदा और इनकम टैक्स स्थित दफ्तरों में यह सुविधा दी जा रही है। जल्द ही ईपीएफओ शहर के विभिन्न इलाकों में कैंप आयोजित करने की योजना बना रहा है।

अगर एंप्लॉयर साइन नहीं करे तो...

पीएफ के पैसे निकालने के लिए एंप्लॉयर का साइन या डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होता है। लेकिन, कुछ मामलों में एंप्लॉयर डॉक्युमेंट साइन करने से इनकार कर देता है। ऐसे में पीएफ कंसल्टेंट अमित पटेल बताते हैं, 'आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगइन करें और सारे डीटेल्स जमा कर दें।

सारी सूचनाएं अपलोड होने के बाद अगर एंप्लॉयर साइन करने से इनकार करता है तो आप कभी भी पीएफ ऑफिस जाकर अपने एंप्लॉयर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।'

पीवीसी पाइप डालने का काम शुरू, सीवर लाइन में नहीं होगी लीकेज

इंदिरापुरम। लाइन में लीकेज और पेयजल के साथ सीवर का पानी आने की समस्या से इंदिरापुरम के लोगों को जल्द ही राहत मिलने जा रही है। जीडीए ने नीतिखंड में नई पेयजल लाइन डालने का काम शुरू कर दिया है। सीमेंट पाइप की जगह जीडीए पीवीसी पाइप डाल रहा है जो लंबे समय तक लीकेज की समस्या नहीं आने देंगें। पहले चरण में नीतिखंड से अच्छसा खंड दो तक लाइन डाली जा रही है। साल के अंत तक पूरे इंदिरापुरम में पाइपलाइन डालने का काम पूरा कर लिया जाएगा। जीडीए ने इंदिरापुरम में करीब बीस वर्ष पाइपलाइन डाली थीं। समय के साथ इंदिरापुरम में ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज की संख्या बढ़ने से ये लाइनें लोगों का बोझ नहीं उठा पा रही हैं। आए दिन लाइन में लीकेज होने से लोगों को पानी नहीं मिलता। इसके साथ ही लीकेज के साथ गंदा सीवर का पानी और गंदगी भी पानी में आती है। इसे देखते हुए जीडीए अब स्वर्ण जयंती पार्क से सात सौ मिलीमीटर मोटी पीवीसी पाइपलाइन डाल रहा है। पहले चरण में अच्छसा खंड दो के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लाइन डालने के बाद लोगों को पेयजल की समस्या से पूरी तरह निजात मिलने का दावा किया जा रहा है।

जीडीए की 30 करोड की जमीन पर गौशाला और मार्केट

गजियाबाद। प्रदेश सरकार का भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी माफियाओं अभियान ना केवल जिला प्रशासन,पुलिस तथा दूसरे विभागों के बीच तालमेल के अभाव में सरकारी महकमों की फाइलों में सीमित होकर रह गया है बल्कि माफिया अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए के खाली पडे भूखंडों पर भी मार्केट खडी करने लगे है। बताते है कि माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने जीडीए की करीब तीस करोड रूपए की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है और जमीन पर गौशाला का संचालन किया जा रहा है। बताते है कि ये खेल जीडीए के प्रवर्तन विभाग के सहयोग से चल रहा है। बदले में एक मोटी रकम की वसूली की जाती है। प्राधिकरण के सूत्र

कहां है एंटी भू माफियां अभियान

बताते है कि एंटी भूमाफिया अभियान सफल बनाने के लिए एक दर्जन से ज्यादाबार लेटर के माध्यम से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला।

यहां बता दे कि प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने का फरमान जारी किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सीमा से लगे गाजियाबाद में इस अभियान का दूर तक भी असर नहीं नजर आ रहा है बल्कि देखा जाए तो मौजूदा में भी भू माफियाओं के हौसले बुलंद है। सूत्र बताते है कि वैशाली सेक्टर एक में जीडीए के द्वारा निर्मित चार मंजिले भवनों से लगे करीब डेढ सौ वर्ग मीटर के भूखंड पर ना केवल मार्केट खडी कर दी गई बल्कि अब मार्केट के साथ तीन मंजिला इमारत का निर्माण किसी भी वक्त देखा जा सकता है। प्राधिकरण के सूत्र बताते है कि वैशाली के सैक्टर तीन में जीडीए की करीब तीस करोड रूपए लागत की बेशकीमती जमीन पर अवैध तरीके से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। जीडीए के अधिकारियों की मानें तो पुलिस और प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण से अभियान सफल नहीं हो रहा है।

सरकार ने रोका फंडा बना निगम के गले की फॉश

गाजियबाद। अवस्थापना निधि के तहत प्रदेश सरकार से मिलने वाली रकम का भुगतान ना होने का मामला निगम अधिकारी एवं पार्षदों के गले की फांश बनकर रह गया है। आर्थिक तंगी से जुझ रहे निगम के पार्षद ये तय नहीं कर पा रहे है कि कैसे विकास के प्रस्तावित कामों को पूरा कराए।

पार्षद ये तय नहीं कर पा रहे है कि अवशेष रकम का भुगतान कराने के लिए किस तरीके से प्रदेश सरकार के सामने दबाव बनाए। वजह प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। अवस्थापना निधि के तहत बकाया राशि किश्तों के तौर पर भुगतान के लिए निगम प्रशासन सरकार पर दबाव बना रहा है।

अधिकारियों की उम्मीद है कि अवस्थापना निधि के तौर पर बकाया 237 करोड में से 50 करोड की रकम जल्द प्राप्त हो जाएगी। आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री से निगम को अवस्थापना निधि के तहत एक बडी रकम सरकार से मिलती है। मेयर आशु वर्मा के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन शहरी विकास मंत्री आजम खां का अवस्थापना निधि के तहत बकाया राशि के भुगतान के मुददे को लेकर तीखा विरोध किया गया था।

दिल्ली में 2 रुपये तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपये तक की कमी आ सकती है। राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट दरों में कटौती करने का मन बना लिया है और इसका ऐलान मंगलवार को हो सकता है। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों की मानें तो यह कटौती 3-4% तक हो सकती है, जिससे दोनों ही कमोडिटीज के दाम डेढ़ से दो रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएंगे। दिल्ली वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'इस बारे में लगभग सहमति बन चुकी है और सब कुछ उसके मुताबिक हुआ तो मंगलवार को वैट कटौती का ऐलान हो सकता है।' उन्होंने कहा कि चूंकि वैट दरों को लेकर पड़ोसी यूपी और हरियाणा सहित कई उत्तरी राज्यों में तीन साल पहले सहमति बनी थी कि रेट एक समान रखना है। किसी भी एक राज्य में कम या ज्यादा रेट से राजस्व असंतुलन पैदा होता है। अब जब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत देने की जरूरत महसूस की जा रही है, तो इन राज्यों को भी भरोसे में लेना जरूरी है। इसी मकसद से मंगलवार को चंडीगढ़ में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूपी के वित्त मंत्रियों की बैठक रखी गई है। उसी दिन कोई ऐलान होगा। यह पूछे जाने पर कि दिल्ली वालों को कीमतों में कितनी राहत मिलेगी अधिकारी ने कहा, 'अंतिम फैसला वित्त मंत्रियों की बैठक में ही होगा, लेकिन अब तक की चर्चा में रेट 4 पर्सेंट तक घटाने पर विचार हुआ है। हालांकि पेट्रोल पर रेट को लेकर तोड़ा मतभेद है, लेकिन डीजल पर एक समान कटौती पर सहमति है।' फिलहाल दिल्ली, यूपी, हरियाणा में पेट्रोल पर करीब 27% और डीजल पर 17% की दर से वैट लगता है। अगर दोनों पर रेट 3-4 पर्सेंट तक घटे तो कीमतें 2 रुपये तक कम हो जाएंगी। पंजाब में डीजल पर रेट तो इतना ही है, लेकिन पेट्रोल पर 35% है। गौरतलब है कि शराब और पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और इन दोनों पर पहले की तरह केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट वसूलती हैं। तेल कंपनियां आज भी पेट्रोल लगभग 40 रुपये प्रति लीटर की दर से जारी करती हैं, लेकिन उस पर 20 रुपये की एक्साइज ड्यूटी और उसके ऊपर 27% (दिल्ली में) वैट के बाद कीमत 70 के पार चली जाती है। उसके बाद पंप डीलरों का कमीशन और कुछ दूसरे मामूली चार्ज जोड़कर कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। इसी तरह डीजल के दाम भी जुड़ते हैं।

प्राइवेट नौकरी से निकाल दिए गए तो भी 3 महीने तक सरकार देगी वेतन, ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारियों को लाभ

नई दिल्ली। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, नौकरी से निकाले जाने या किसी अन्य वजह से नौकरी छूटने पर भी 3 महीने तक वेतन मिलता रहेगा, बशर्ते कर्मचारी ईएसआईसी यानि कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़ा हो।

बुधवार को ईएसआईसी ने एक नयी योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार होने पर नकद राहत मिलेगी।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी।

'श्रमिकों के न्याय में रोडा न बने जिलाधिकारी'

नोएडा। नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के लाखों श्रमिकों के मामले में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद न्याय में विलंब की आशंका बढ़ गई है। इसको लेकर व्यापक विरोध मुखर होने लगा है। वहीं इस बावत प्रशासन का तर्क है कि यह व्यवस्था पहले से कायम थी अब उन्होंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है।

दरअसल जिलाधिकारी ने उप श्रमायुक्त कार्यालय को निर्देश दिये हैं कि श्रमिकों की शिकायतों को पहले उनके कार्यालय भेजा जाए। वहां से मार्क होने के बाद शिकायतें निस्तारण के लिए डीएलसी के पास भेजी जाएंगी। समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष तथा वरिष्ठ मजदूर नेता रजब खान का कहना है कि इस औपचारिकता में समय अधिक लगेगा तथा श्रमिकों के न्याय में विलंब होगा। यह व्यवस्था श्रमिकों के हक में नहीं है।

हिन्द मजदूर सभा के महमंत्री आरबी

- निर्णय के खिलाफ सपा व अन्य श्रमिक संगठन लामबंद

सिंह चौहान ने बताया कि इस निर्णय से श्रमिकों तथा श्रमिक संगठनों में काफी रोष है। यदि यह व्यवस्था नहीं बदली गयी तो व्यापक विरोध किया जाएगा तथा जरूरत पड़ी तो व्यापक विरोध किया जाएगा तथा जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की मांग की जाएगी।

बता दें कि इसको लेकर संयुक्त ट्रेड मोर्चा की एक बैठक भी बृहस्पतिवार को की गयी जिसमें सभी श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश स्तर के पदाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने उद्यमियों खासकर उद्योग बंधुओं पर नरम रूख रखने के उद्देश्य से यह निर्देश दिये हैं जो पूरी तरह तुगलकी है। इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
उद्योग–जगत
06
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, सितम्बर, 2018
P.

प्रदेश सरकार का खर्चों में कटौती के लिए एक नया फरमान

अनुपयोगी पद तमाम विभाग प्रमुख करें समाप्त

- निजी वाहनों को अब अनुबंध पर नहीं लगाया जा सकेगा
- विदेश यात्रा आदि पर खर्चों में कटौती करें विभाग प्रमुख
- अधिकारी बदलने पर नए फर्नीचर खरीद व दफतर आदि की साज सज्जा के खर्च पर भी लगी रोक

गाजियाबाद। जहां युवाओं को पढाई हासिल करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है और शिक्षित युवा पढाई पर एक बडी रकम खर्च करने के बाद भी दर दर की ठोकरे खा रहा है ठीक दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार ने तमाम विभाग प्रमुखों को एक नया फरमान जारी किया है। खर्चों में कटौती के दिशा में तमाम अनुपयोगी पद पूरी तरह से खत्म करने के आदेश दिए गए है। ऐसे तमाम कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए यथा संभव दूसरे विभागों में समायोजित करने के लिए कहा गया है।

प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय की तरफ से विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने तमाम विभाग प्रमुखों को लेटर भेजा है। इस लेटर के माध्यम से कहा गया कि विगत एक दशक में विभागों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने से कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त विभागों में कार्य क्षेत्र के बदलाव के साथ कतिपय विभागों के कार्यभार में कमी आयी है। बदले हुए परिवेश में अनुपयोगी पदों को चिन्हित कर समाप्त करते हुए ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को यथासंभव अन्य पदों या अन्य विभागों में समायोजित करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए। चिकित्सा एवं पुलिस विभागों को छोडकर समान्यतः नए पद स्वीकृत न किया जाए। सेवा नियमों के विपरित नियत वेतन,दैनिक वेतन,संविदा इत्यादि के आधार पर कर्मचारी नियुक्ति करने पर प्रतिबंध पूर्ववत बना रहेगा। अपरिहार्यता की स्थिति में कार्यों को बाहय एजेंसी सेवा प्रदाता से कांटेक्ट करते हुए कार्य कराए जाए। चतुर्थ श्रेणी के पदो के साथ साथ कतिपय विशिष्ठ/ तकनीकी कार्य के लिए सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री एवं अन्य इसी प्रकार के रिक्त होने वाले पदों पर नियमित नियुक्तियां ना की जाए। यह समस्त सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराए जाए। विभिन्न विभागों में सलाहाकार,अध्यक्ष,सदस्य आदि अस्थायी प्रकृति के पदों पर नियुक्ति की जाती है।

इन पदो के लिए सहयोगी स्टाफ की आवश्यकता हेतु कोई पद सृजित ना की किए जाए। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से अथवा आउटसोर्सिंग स्टाफ से की जाए। राज्य की योजनाओं की समीक्षा एक निश्चित अंतराल पर की जाए तथा जो योजनाएं अनुपयोगी है उन्हें समाप्त करने पर विचार किया जाए। राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों की अनुमन्य दरों के अनुरूप ही टीए, डीए, एचआरए, सीसीए, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान अनुमन्य होगा। यदि किसी संस्था में इससे इतर भत्तें दिए जा रहे हो तो उन्हें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाए।

मुख्य सचिव की तरफ से जारी फरमान में ये भी स्पष्ट किया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर किए जा रहे भारी खर्च के दृष्टिगत प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने तथा निजी विधालयों से प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के उददेश्य से अध्यापक, छात्र अनुपात का कडायी से पालन किया जाए तथा सरप्लस अध्यापकों का यथासंभव समायोजन आवश्यकता अनुसार अन्यत्र किया जाए। इसके साथ साथ विदेश यात्राओं,मुद्रण एवं प्रकाशन,व्यवसायिक सेवाएं एवं विशेष सेवाओं के साथ विज्ञापन एव प्रसार तथा दूसरे सरकारी कार्यालयों के रखरखाव में कटौती की जाए।

नव सृजित जिलों एवं मंडलों को छोडकर मुख्यालयों पर नए कार्यालय/आवासीय भवन निर्मित ना किए जाए। केवल इस चलते की पदधारक बदल गया है के नाम पर नया फर्नीचर व साज सज्जा की व्यवस्था ना की जाए। यदि अनुबंध पर टैक्सी के रूप में वाहन के रूप में वाहन शासकीय कार्य के लिए लिया जाना है तो विभाग अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करने के बाद ही अनुबंध पर वाहन ले सकते है। किसी भी स्थिति में निजी वाहनों को अनुबंध पर ना लिया जाए।

यूटीआई का इलाज नहीं होने से डैमेज हो सकती है किडनी

- किडनी फेलियर युरीनरी ट्रैक्ट संक्रमण (यूटीआई) का इलाज न होने का गम्भीर परिणाम होता है
- महिलाओं के लिए यूटीआई संक्रमण की चपेट में आने से बचाव के लिए जरूरी है स्वच्छता
- हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में गाजियाबाद 36वें रैंक पर, स्वच्छता का अभाव

गाजियाबाद। यूरीनरी ट्रैक्ट का एक साधारण सा संक्रमण भी अगर समय पर इलाज करके ठीक न किया जाए तो किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। हालिया स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में शहर स्वच्छता से बहुत दूर पाया गया, सर्वे में शहर 36वें रैंक पर रहा है। डॉक्टर यह उम्मीद कर रहे हैं कि शहर में यूटीआई के मामले कम होंगे।

महिलाओं में मीनोपॉज के बाद खतरा बढ जाता है, क्योंकि इसके बाद उनमें सकुर्लेटिंग एस्ट्रोजन में कमी आ जाती है जिसके चलते युरीनरी ट्रैक्ट में बदलाव आता और संक्रमण होने का खतरा बढ जाता है।

कोलम्बिया एशिया हॉस्पिटल, गाजियाबाद की कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रीशियन एवम गायनेकॉलजिस्ट डॉ. रंजना बेकन कहती हैं,ह्हम हर महीने यूटीआई के बहुत सारे मरीज देखते हैं। युरीनरी ट्रैक्ट संक्रमण से पीडित हर व्यक्ति को किडनी फेलियर नहेन होता है। अधिकतर मामलों में, यूटीआई का इलाज बेहद आसानी से हो जाता है, इससे पहले कि वह किडनी को डैमेज करे। यद्यपि, यूटीआई की वजह से समस्या तब बढ जाती है जब इससे सम्बंधित अन्य समस्याएँ वॉटर रिटेंशन के साथ आती हैं, जैसे कि एंलार्ज्ड प्रॉस्टेट ग्लैंड (पुरुषों में) अथवा किडनी में होने वाली पथरी का अगर समय पर इलाज न किया जाए और संक्रमण लगातार जारी रहे। कम उम्र के बच्चों मेंस्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण की वजह से जो यूटीआई होता है उसमें तेज बुखारभी साथ में होता है, और इसमें तुरंत उपयुक्त इलाज की जरूरत होती है अन्यथा कई बार यह किडनी डैमेज का कारण बन सकता है।

बैक्टीरियल संक्रमण जो ब्लैडर, युरेथ्रा को प्रभावित करते हैं और किडनी व यूट्रस को कभी कभार ही प्रभावित करते हैं, के लिए आमतौर पर स्वच्छता की खराब स्थिति जिम्मेदार होती है। यूटीआई के लक्षणों में बार-बार और बहुत तेजी से पेशाब आना, बुखार, पेशाब से बहुत तेज बदबू, पेशाब करते समय दर्द अथवा जलन का एहसास, मितली अथवा उल्टी आना, मांसपेशियों और पेट में दर्द महसूस होना आदि। मल्टीड्रग-रेजिस्टेंस वाला यूटीआई एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल का परिणाम माना जाता है, यही वजह है कि इस संक्रमण को ओरल एंटीबायटिक्स के जरिए ठीक करना कठिन होता है। बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स का अनुपयुक्त इस्तेमाल ऐसे संक्रमणों को बढावा दे सकता है जो किडनी डैमेज के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस इफेक्शन भी हो सकता है। महिलाओं में यूटीआई का संक्रमण पुरुषों की तुलना में काफी अधिक होता है क्योंकि महिलाओं का मूत्रमार्ग छोटा होता है, ऐसे में बैक्टीरिया आसानी से पेशाब की थैली तक पहुंच जाते हैं।

अगर यूटीआई का इलाज न हो तो यह क्रॉनिक किडनी इंफेक्शन (फाइलोनेफ्राइटिस) का कारण बन सकता है। अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष जिन्हें प्रॉस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है उन्हें भी इस तरह का ब्लॉकेज हो सकता है, जो यूटीआई के लिए जिम्मेदार होता है। जिन लोगों के पेशाब की थैली में लम्बे समय तक कैथेटर (ट्यूब) लगा होता है उन्हें भी संक्रमण का खतरा अधिक रहता है क्योंकि कैथेटर पर जमा बैक्टीरिया आसानी से पेशाब की थैली में पहुंच सकते हैं और उसे संक्रमित कर सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए एक निश्चित अंतराल के बाद कैथेटर बदल देने की सलाह दी जाती है। हर साल युरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई) से प्रभावित कम से कम 5 मरीज किडनी फेलियर का सामना करते हैं जिसकी वजह है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का बढता खतरा।

डायबीटीज से पीडित लोग अपने शरीर की प्रतिरोधक सिस्टम में बदलाव महसूस कर सकते हैं, जिससे उन्हें युरीनरी संक्रमण होने का खतरा बढ जाता है। जिन लोगों के युरीनरी ट्रैक्ट में रुकावट होती है, जैसे कि किडनी में पथरीहो, उन लोगों को यूटीआई होने का खतरा अधिक रहता है।

यूटीआई की वजह से होने वाली अन्य जटिलताओं में शामिल है गर्भवती महिलाओं द्वारा सामान्य से कम वजन वाले बच्चे को जन्म देना अथवा समय से पहले ही नवजात का जन्म हो जाना; बार-बार होने वाले युरेथराइटिस से पुरुषों का मूत्रमार्ग पतला हो जाता है, गोनोकोकल युरेथराइटिस; और सेप्सिस जैसे मामले देखे गए हैं, जो कि संक्रमण का जीवन घातक रूप है, खासतौर से तब जब संक्रमण युरीनरी ट्रैक्ट से होते हुए किडनी तक पहुंचने का रास्ता बना लेता है।

खुले में शौच से रोकना पड़ रहा निगम स्टाफ को भारी

- झगडे एवं हाथापाई का बढा खतरा
- टायलेट की उपलब्धता है नहीं
- लेटरों के बाद भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिला कभी खुले में शौच से मुक्त हो पाएगा इसकी दूर तक भी संभावना नजर नहीं आ रही है बल्कि शहर भर में जगह जगह नगर निगम के द्वारा तैनात स्टाफ मुश्किल में है। वजह इस स्टाफ और खुले में शौच के लिए जाने वाले लोगों के बीच हाथापाई एवं झगडे का खतरा बड रहा है। निगम के वसुंधरा जोन के प्रभारी सुनील राय की मानें तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सचल टायलेट उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से एक दर्जन लेटर के माध्यम से आग्रह किया जा चुका है,उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे खुले में शौच के लिए जाने वाले लोगों को रोका जाए। पूरे अभियान के प्रभारी मुख्य लेखा अधिकारी एके मिश्रा के सामने भी वस्तु स्थिति रखी जा चुकी है। इसके बाद भी ज्वलंत समस्या का हल नजर नहीं आ रहा है। टैक्स अधीक्षक एवं दूसरे स्टाफ की ड्यूटी सुबह पांच बजे से खुले में शौच के लिए जाने वाले लोगों को रोकने के परिणाम स्वरूप जोन के दूसरे काम चैपट होकर रह गए है। उन्होंने कहा कि अभियान में सबसे बडी अडचन जीडीए से तालमेल का अभाव है। निगम सीमा के वसुंधरा, वैशाली क्षेत्र में लोगों को खुले में शौच से रोका जाए तो वह इंदिरापुरम सीमा में चले जाते है और खुले में शौच करते हुए देखे जा सकते है। कम से कम चार सचल टायलेट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। उनकी ये समझ से दूर है कि जो पहले सचल टायलेट की व्यवस्था की गई थीं वो कहां गए।

यहां बता दे कि नगर निगम के आला अधिकारियों के द्वारा एक बार फिर से गाजियाबाद को प्रदेश में खुले में शौच से मुक्त कराने के नाम पर वाहवाही लूटने को तमाम स्टाफ की डयूटी लगा दी है। ये स्टाफ खुले में शौच जाने वालों को रोकने के लिए लगाया गया है। जबकि अभी भी शहर के अनेक स्थान ऐसे है जहां पर वैकल्पिक कदम नहीं उठाए गए है। खासकर झुग्गी झोपडी के लोग अभी भी खुले में शौच करने जाते हुए देखे जा सकते है। निगम के स्टाफ की मानें तो उनके लिए एक नई सिर दर्द पैदा हो गया है। एक महिला को खुले में शौच करने जाने से रोका तो वह निगम प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन के पास ही शौच करने बैठ गई।

उद्योग विहार राष्ट्रीय

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, सितम्बर, 2018

UAN नंबर के जरिए पता करें अपना ईपीएफ (EPF) बैलेंस

EPFO दे सकता है यह खुशखबरी!

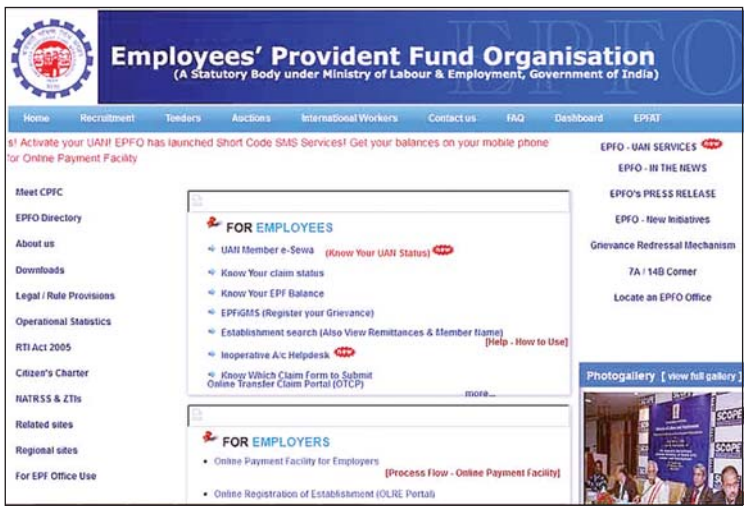

EPFO: 5 करोड़ PF खाताधारकों को लगा ये बड़ा झटका, वेतनभोगियों को होगा नुकसान ऑनलाइन PF क्लेम करने से पहले ध्यान रखें ये 5 बातें –

नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए EPF यानी भविष्य निधि बेहद अहम फंड है। अधिकतर जानकारों यही सलाह देते हैं कि EPF में जमा पैसा रिटायरमेंट तक न निकाला जाए। हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के वेतन से PF की एक तय राशि कटती है। आपके PF में कितना बैलेंस है इसकी जानकारी के लिए आपको हर बार कंपनी के HR के पास जाना पड़ता है लेकिन अब ये झंझट खत्म हो गई है। हम आपको कुछ ऐसे आसान स्टेप बताएंगे जिससे आप अपना EPF बैलेंस घर बैठे ही पता कर लेंगे। इसके जरिए आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि आपके पीएफ अकाउंट में लगातार पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं।

ऑनलाइन चेक करें EPF

आपके भविष्य निधि खाते यानि PF में कितनी रकम जमा है, इसकी जानकारी के लिए EPFO की वेबसाइट पर लॉग इन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना जरूरी है। EPFO ने 2014 में UAN शुरू किया था ताकि इसके जरिए आप अपने खाते की ऑनलाइन जानकारी ले सकें। इस नंबर के जरिए साइट पर रजिस्टर हों, खाते की पासबुक देखें और चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर लें। यह भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ओर से कितना कंट्रीब्यूशन किया गया। अपनी डिटेल अपडेट करें इसके अलावा, आप यहीं से अपना UAN कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, केवाईसी (नो योर कस्टमर) डीटेल भी अपडेट कर सकते हैं। इस इंटरफेस का इस्तेमाल करने के लिए बेहद जरूरी है कि आपके पास UAN नंबर हो। अपना UAN अकाउंट एक्टिवेट करिए और पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद EPF पासबुक डाउनलोड करिए या अन्य जरूरी अपडेशन कर लीजिए।

PF निकासी के नए नियम

-पढ़ाई, शादी और मकान के लिए इतना निकाल सकते हैं पैसा

-नौकरी जाने के 30 दिन बाद 75% निकाल सकते हैं PF का पैसा

-सिर्फ 60% रकम ही निकाल सकेंगे PF अकाउंट से

बिना UAN के भी चेक कर सकते हैं EPF बैलेंस

अगर आपके पास UAN नहीं है तो भी आप अपना EPF चेक कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपका EPF खाता संख्या क्या है। यह खाता संख्या आपको अपनी पे-स्लिप (सैलरी की रसीद) पर लिखी हुई मिल जाएगी। साइट पर जाकर अपना राज्य चुनें और फिर रीजनल ऑफिस चुनें। ये डीटेल वहां टाइप करने के बाद आपके पास EPF बैलेंस से संबंधित SMS आ जाएगा।

अगर आपको ऑनलाइन EPF बैलेंस पता करने में परेशानी हो रही है तो आप SMS के जरिए भी अपना EPF पता कर सकते हैं। EPFO SMS सेवा के जरिए भी आपको आपके भविष्य निधि खाते में मौजूद राशि के बाबत जानकारी देता है। 07738299899 नंबर पर रटर करिए। वैसे यह सुविधा केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने UAN एक्टिवेट करवाया हुआ है।

कैसे भेजे SMS : SMS भेजते समय मेसेज बॉक्स में लिखें EPFOHO UAN, इसके आगे जिस भाषा में जानकारी चाहते हैं उसके पहले तीन अक्षर लिखें, उदाहरण के लिए– EPFOHO UAN ENG लिखकर 07738299899 नंबर पर SMS भेजेंगे तो इंग्लिश में जानकारी आ जाएगी। दरअसल यह सेवा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। एसएमएस के जरिए कैसे पता करते हैं ईपीएफ बैलेंस, इसकी जानकारी आगे दी गई है। ऐसे चेक करें अपना बैलेंस अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टीविटी नहीं है तो अपने रजिस्टर्ड नंबर से एक SMS भेजकर आप पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले uan-members.epfoservices.in में जाकर आपको अपना एक एकाउंट बनाना होगा जहां पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं तो सीधे मोबाइल से एक मैसेज करना होगा। बस इस बात का ध्यान रखें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हो उसी नंबर से एसएमएस करें। अब क्या करें मोबाइल से एसएमएस करने के लिए मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें EPFOHO UAN ENG मैसेज टाइप करने के बाद उसे 7738299899 नंबर पर भेज दें। थोड़ी देर में आपके नंबर पर पीएफ बैलेंस से जुड़ी सारी जानकारियां आ जाएगी। अन्य भाषाओं में भी मिलेगी बैलेंस की जानकारी अगर आप किसी दूसरी भाषा में एसएमएस पाना चाहते हैं तो इसके लिए भाषा बदलने का ऑप्शन भी दिया गया है जैसे, English- ENG ,Telugu- TEL , Punjabi- PUN , Gujarati- GUJ , Marathi- MAR , Malayalam- MAL , Tamil- TAM , Kannada- KAN , Bengali- BEN, मिस्ड कॉल सेवा EPF जानने का ये सबसे आसान तरीका है। ना एसएमएस, ना इंटरनेट बस आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFO द्वारा दिए गए नंबर पर मिस्डकॉल करना होगा और आपको आपके EPF बैलेंसे की जानकारी EPFO ने बैलेंस की जानकारी के लिए 01122901406 नंबर जारी किया है जिसपर आपको सिर्फ मिस्डकॉल देना है इसके बाद आपके मोबाइल पर EPF बैलेंस की जानकारी भेज दी जाएगी। M–सेवा ऐप आज के दौर में हर व्यक्ति स्मार्ट फोन का प्रयोग कर रहा है। अगर आप भी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो EPFO की मोबाइल ऐप M–सेवा का प्रयोग करें। इस सेवा का उपयोग करने के लिए M–सेवा एप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंस्टॉल होना चाहिए। एप पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल देनी होगी बाद में आपको बिना किसी झंझट के EPF बैलेंस की जानकारी मिलती रहेगी।

हिडन मजदूर सभा ने दिया धरना

नोएडा। मै.राहुल मिश्रा डिजाइन प्रा. लि बी-10 सेक्टर सात, व सेकुलरिट्रास प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 14 व अन्य प्रतिष्ठानों से निकाले गए लगभग 400 मजदूरों ने हिंद मजदूर सभा के महामंत्री आरपी सिंह चौहान के नेतृत्व में मजदूरों ने भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पंडित दीनदयाल मार्ग पर धरना दिया और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ज्ञापन दिया।

इस दौरान भाजपा नेताओं की शह पर पुलिस ने धरने को गैर कानूनी घोषित करते हुए हिंद मजदूर सभा के महामंत्री आरपी सिंह चौहान के साथ-साथ सभी 400 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया। कामरेड रितेश कुमार झा ने कहा कि श्रमिक की समस्याओं की अनदेखी अफसरों द्वारा लगातार की जा रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी श्रमिकों का शोषण लगातार जारी है।

कुत्ता काटे के इंजेक्शन के लिए करें इंतजार

गाजियाबाद। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को कुत्ते ने काट लिया है तो उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में लेकर गलती से भी ना जाए,हो सकता है कि अस्पताल में पहुंचने पर आपको बैरंग लौटना पडे। जी हां जिले के अधिकांश अस्पतालों में कुत्ता काटे के इंजेक्शन ही नहीं है। संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल के स्टाफ की मानें तो प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों में कुत्ता काटे के इंजेक्शन नहीं है। सूत्रों की मानें तो सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाईयों का भी टोटा है। मांग के अनुरूप जीवन रक्षक दवाईयां भी पीछे से नहीं मिल रही है। ये स्थिति उस वक्त है जब केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों का स्वरूप बदलने के दावे किए जा रहे है। दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति ये है कि स्थानीय सांसद और शहर विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री है, लेकिन किसी के पास भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखने के लिए वक्त नहीं है। हवा में ही लंबी बातें हो रही है। जीटीरोड स्थित एमएमजी अस्पताल परिसर के जिस कक्ष में कुत्ता काटे के इंजेक्शन लगाए जाते है। वहां पर अलग से पर्ची नोटिस के तौर पर चस्पा की गई है कि कुत्ता काटे के इंजेक्शन नहीं है। आने के बाद ही लग पाएंगे। अस्पताल के स्टाफ की मानें तो पिछले तीन माह से पीछे से कुत्ता काटे के इंजेक्शनों की सप्लाई नहीं हो रही है। ये स्थिति सिर्फ गाजियाबाद तक ही सीमित नहीं बल्कि प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों की है।

जीडीए के कम्प्यूटर विभाग को है इलाज की आवश्यकता

एक बडी रकम खर्च करने के बाद भी साफ्टवेयर एक दशक पुराना

गाजियाबाद। जहां प्रदेश सरकार के द्वारा ये महसूस किया जा रहा है कि तमाम सरकारी महकमों में कम्प्यूटराइजेशन होने के बाद कार्य शैली में अमूल बदलाव आया है,लेकिन देखा जाए तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए में कम्प्यूटराइजेशन के नाम पर केवल हवा में ही लकीर पीटने का काम हो रहा है। कम्प्यूटर विभाग के स्टाफ की मानें तो कहने के लिए अलग से कम्प्यूटर विभाग है,लेकिन ये महकमा किन हालातों के दौर से गुजर रहा है शायद कोई देखने वाला नहीं है। स्टाफ की मानें तो मौजूदा में भी एक दशक पुराने साफट वेयर पर प्राधिकरण टीका हुआ है। जबकि पिछले दो दशक के दौरान कम्प्यूटराइजेशन के नाम पर एक मोटी रकम खर्च की जा चुकी है। बिगडे हालात के लिए विभाग प्रमुखों के द्वारा महकमें को गंभीरता से नहीं लिया जाना है। स्टाफ कहता है कि विभाग के प्रभारी की कमान ऐसे लोगों के हवाले की गई है जिन्हें दूर तक किसी तरह का ज्ञान नहीं। तीन सहायक प्रोग्रामर होने के बाद भी उनका दूर तक लाभ हासिल नहीं किया जा रहा है।

यू तो अभी हाल में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा जारी फरमान को देखा जाए तो उससे लगेगा कि तमाम सरकारी महकमों में कम्प्यूटराइजेशन के बाद से बहुत कुछ बदलाव आ गया है। इस बदलाव को देखते हुए विभागों में अतिरिक्त स्टाफ की छुटटी किए जाने पर जोर दिया गया है। प्राधिकरण कार्यालय में वैसे तो परिसर के तीसरे तल पर अलग से कम्प्यूटर विभाग है,लेकिन ये किस हालात में है उसे देखने के लिए शायद किसी के पास भी वक्त नहीं है। परिसर की सीलिंग की स्थिति ही बद से बदतर है। मामूली सी बरसात के दौरान छत से पानी टपकता है।

जो कम्प्यूटर बेकार हो गए,उन्हें हटवाने के साथ नए कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं की गई है।

प्राधिकरण सूत्रों से पता चला कि हाल में कम्प्यूटर विभाग में तैनात धर्मेंद्र त्यागी को मोबाइल एप आदि से जुडा दायित्व दिया गया,श्री त्यागी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने का आग्रह किया गया। लेटर में साफ किया गया कि मोबाइल एप आदि के कार्य महत्वूपर्ण कार्य है। सहायक प्रोग्रामर की देखरेख में दायित्व दिया जाना चाहिए,हैरत का पहलू ये है कि श्री त्यागी के प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया गया बल्कि श्री त्यागी की सैलरी का ही भुगतान रोक दिया गया। पिछले चार माह से श्री त्यागी सैलरी का भुगतान ना किए जाने को लेकर दुविधा की स्थिति में है। हालांकि जीडीए सचिव संतोष राय ने कहा कि कम्प्यूटर विभाग की कार्यशैली में जल्द सुधार किया जाएगा।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

08 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, सितम्बर, 2018

सक्सेस करीना कपूर की अनसक्सेस लव स्टोरी

बॉलीवुड की बेबो यानि एक्ट्रेस करीना कपूर खान 38 साल की हो गयी है। कपूर खानदान की लाड़ली करीना ने महज 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया था। करीना कपूर अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अपने स्टाइल के लिए बॉलीवुड में जानी जाती है। शादी, बच्चा होने के बावजूद भी उनका नाम बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस की लिस्ट में नाम शुमार है। जबकि बॉलीवुड में ऐसा कहा जाता है की ज्यादा उम्र की एक्ट्रेस को रोल नहीं मिलता लेकिन करीना ने इस स्टेटमेंट को गलत साबित किया और वीरे दे वेडिंग से एक और बार बड़ी ही जबरदस्त एंट्री की। करीना कपूर खान आज सैफ अली खान की वाइफ और पटौदी खानदान की बहु है। उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है जिसका नाम तैमूर अली खान है। सैफ से शादी से पहले करीना के दिल पर किसी और का राज था, यह बात तो सभी को पता ही होगी, कि करीना और शाहिद कपूर एक दूसरे को डेट कर चुके है। लेकिन शाहिद से पहले उनका नाम बॉलीवुड के एक और खान से भी जुड़ चुका है। शाहिद कपूर को डेट करने से पहले बेबो का अफेयर बॉलीवुड के डैशिंग एक्टर फरदीन खान से भी रह चुका है। फरदीन और करीना कपूर की नजदिकियां तब बढ़ी जब वो दोनो साख में फिल्म खुशी की शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने फिदा और देव जैसी फिल्मों में भी एक साथ काम किया। और इसी दौरान इनका प्यार परवान चढ़ गया था। नकी जोड़ी को लोग इतना पसंद कर रहे थे कि इसी दौरान वह दोनों बहुत सारे कमर्शियल एड्स में भी साथ नजर आये। लेकिन कहते है न कि किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता, होना क्या था शायद इन दोनो के प्यार को किसी की नजर लग गई थी। कुछ दिन बाद करीना और फरदीन एक दूसरे से अलग हो गये और इस अलगाव का कारण थे शाहिद कपूर। यहीं वो टाइम था जब फरदीन खान से ब्रेकअप के बाद करीना की जिंदगी में शाहिद की एंट्री हुई। अखबारों में छपि खबरों के अनुसार करीना कपूर के बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद सबसे पहला अफेयर ऋतिक रोशन से हुआ जब वह दोनों फिल्म' कहो न प्यार है' कि शूटिंग कर रहे थे। लेकिन बाद मे करीना ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और इसके बाद से ही करीना और ऋतिक रोशन के रिश्ते में मन –मुटाव शुरू हुआ। कहा जाता है के करीना ने इस फिल्म में काम करने से इस लिए मना कर दिया क्योंकि करीना को फिल्म 'कहो न प्यार है' में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। इसी दौरान उन्हें जे.पी .दत्ता कि फिल्म रिफ्यूजी (2000) में काम करने का ऑफर दिया गया। और करीना को इस फिल्म के लिए फि ल्मफेअर अवार्ड भी मिला।

लेकिन करण जौहर कि फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' कि शूटिंग के दौरान फिर से दोनों कि नजदीकिया बड़ी, लेकिन सुजैन खान को इस बात का पता चल गया था और जिसके बाद सुजैन ने ऋतिक रोशन को डेडलाइन दे दी थी। इसी कि वजह से फिल्म 'मैं प्रेम की दीवानी हूँ' के बाद दोनों आज तक किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आये करीना का शाहिद के साथ रिलेशन उनके सबसे चर्चित अफेयर में से एक था। शाहिद और करीना कि नजदीकिया फिल्म 'फिदा ' कि शूटिंग के दौरान बड़ी। दोनों 36 चाइना टाउन, चुप–चुप के, जब वी मेट, और मिलेंगे– मिलेंगे जैसी फिल्मों में एक साथ नजर आये, करीना और शाहिद का रिलेशन 3 साल तक चला लेकिन यह तब अलग हुए जब करीना कि लाइफ मे सैफ कि एंट्री हुयी। सैफ और करीना फिल्म टशन कि शूटिंग के दौरान नजदीक आये। बॉलीवुड कि बेबो अपने इंस्टेंट जवाब के लिए काफी जानी जाती है उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, किसी से बिना डरे अपनी बात खुलकर कहने में वह बहुत माहिर है।

करीना कपूर न सिर्फ फिल्मों के जरिये बल्कि अपने अपीरियंस के चलते भी हर बार एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया। इनके जीरो साइज और प्रेगनेंसी स्टाइल का ट्रेंड भी बहुत चला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने छोटे कपड़े पहनने के मुद्दे पर कहा कि 'एक माँ छोटे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती, ये कहाँ का रूल है और किसने बनाया, करीना ने आगे कहा कि जिसका जो मन हो वो वह कपड़े पहन सकता है, चाहे वो एक लड़की हो या फिर एक माँ, साथ मे उन्होंने यह भी कहाँ कि बस आप पर वह कपड़े अच्छे लगने चाहिए, आप का फिगर अगर ठीक हो तो आप कुछ भी पहन सकती है, उन्होंने कहा मेरी सासू माँ शमीर्ला टैगोर जीन्स, ड्रेस पहनती हैं और वह उन कपड़ो में बेहद खूबसूरत लगती हैं। करीना कपूर खान अब तक छः फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फुटबॉलर हैं विराट कोहली के फैन, बताया महान

इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आने वाले सीजन में जमशेदपुर एफसी से करार करने वाले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फुटबॉलर टिम काहिल ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की. टिम काहिल भारतीय कप्तान के मैदान के अंदर और बाहर हासिल की गई उपलिब्धयों से खासे प्रभावित हैं. इंग्लिश क्लब एवरटन एफसी के लिए खेल चुके इस स्ट्राइकर ने कहा कि वह कोहली को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं. काहिल, कोहली को खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण भी मानते हैं. आईएसएल मीडिया–डे से इतर बात करते हुए काहिल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में, भारतीय क्रिकेट में से जो सर्वकालिक महान खिलाड़ी की गिनती की जाती है उनमें सचिन तेंदुलकर का नाम शामिल है. इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब, जाहिर सी बात है विराट कोहली भी हैं क्योंकि मुझे उनका यहां तक का पहुंचने का सफर पसंद है. उन्होंने कहा, वह काफी मेहनती, विनम्र हैं. उन्होंने काफी बलिदान दिया है. वह आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कोहली जिस तरह से भारतीय क्रिकेट को वापस दे रहे हैं, वह शानदार है. मैं उन्हें सोशल नेटवर्क पर फॉलो करता हूं. टिम काहिल ने अपने देश के लिए चार विश्व कप खेले हैं. बता दें कि विश्व के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज कोहली पिछले तीन साल से बेहतरीन फार्म में चल रहे हैं. विराट कोहली इस समय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे हैं. हालांकि, इंग्लैंड दौरे से वन–डे और टेस्ट मैच सीरीज हार कर लौटी टीम इंडिया को हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा है. भारत 3 मैचों की वन–डे सीरीज 1–2 से और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1–5 से हारा था. इंग्लैंड में मिली इस हार के लिए विराट कोहली की कप्तानी, टीम सलेक्शन और खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर कई सवाल उठाए गए. इस सीरीज में कप्तान विराट कोहली ने सीरीज के दौरान 2 शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से 593 रन बनाए. इतने रन बनाने के साथ–साथ विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए. विराट कोहली ने इस साल के शुरू में दक्षिण अफ्रीका में हुई टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज और टी–20 सीरीज में बढ़िया प्रदर्शन किया था. हालांकि वे टेस्ट सीरीज में वे टीम को जीत नहीं दिला सके और सीरीज में एक ही टेस्ट जीत सके, लेकिन वनडे में शानदार खेल दिखाते हुए विराट ने विदेशी सरजमी पर रिकॉर्ड जीत हासिल की. विराट कोहली ने 71 टेस्ट मैचों में 23 शतकों के साथ 6147 रन बनाए हैं. वहीं, 211 वन–डे में विराट 35 शतक लगाकर 9779 रन बना चुके हैं. विराट को साल 2012 और 2017 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाए जा चुके हैं. वे काफी लंबे समय से आईसीसी की वनडे और टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं।

कास्टिंग काउच के लिए तैयार नहीं हुई तो एक्ट्रेस को 8 महीने तक नहीं मिला काम

अदिति राव हैदरी आज बॉलीवुड में एक बड़ा नाम हैं। अदिति ने अपने करियर की शुरूआत दक्षिण सिनेमा से की थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में मेहरूनीसा के किरदार में नजर आ चुकीं अदिति फिलहाल निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। रॉयल खानदान से ताल्लुकात रखने के बावजूद अदिति को किसी आम लड़की की तरह ही फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना पड़ा है। कई अदाकाराओं की तरह उन्हें भी कास्टिंग काउच के कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा है। अदिति ने अपने इस अनुभव के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हुए कहा कि एक दौर ऐसा था जब मुझे भी ऐसी स्थिति से दो चार होना पड़ा था लेकिन मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल रही। हालांकि अपने फैसले के चलते मुझे कई बार काम से भी हाथ धोना पड़ा और इस बात के चलते मैं कई बार इमोश्नल भी हो जाती थी, हालांकि मुझे कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं हुआ लेकिन मुझे रोना आ जाता था क्योंकि मुझे इतना बुरा लगता था कि कास्टिंग काउच जैसी घटनाएं सच्ची होती थी और लड़कियों को इतने खराब स्तर पर ट्रीट किया जाता था। मुझे लगता था कि आखिर कोई कैसे मुझसे इस तरीके से बात कर सकता है? उन्होंने आगे कहा कि उस घटना के लगभग आठ महीनों बाद तक मुझे कोई काम नहीं मिला लेकिन मुझे लगता है कि मेरे फैसले ने मुझे मजबूत बनाया है। मेरे साथ जब ये घटना हुई थी, तब साल 2013 चल रहा था, ये वही साल था जब मेरे पिता का देहांत हुआ था, ऐसे में वो साल मेरे लिए बेहद मुश्किलों भरा था लेकिन 2014 के बाद से मेरे लिए चीजें बेहतर होती चली गई। कभी कभी आपको स्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है और फिर बेहतर होना पड़ता है। कास्टिंग काउच एक स्टिग्मा है जो एंटरटेन्मेन्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। जहां कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने इसके खिलाफ अपनी खुल कर राय रखी है, वहीं कई ऐसे भी हैं जिनके करियर तक दांव पर लग गए हैं। खास बात ये है कि अदिति ने उस दौर का मजबूती से सामना किया है और आज वे अपने करियर को नई उड़ान दे पाने में कामयाब रही हैं।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901/4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460/9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह